

*This question paper contains 7 printed pages.*

7900

Your Roll No. ....

**LL.B. / V Term**

**ES**

**Paper LB-5037 : ENVIRONMENTAL LAW**

**Time : 3 hours**

**Maximum Marks : 100**

*(Write your Roll No. on the top immediately  
on receipt of this question paper.)*

**NOTE:—** *Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

**टिप्पणी:—** इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

*Attempt any five questions.  
All questions carry equal marks.*

*किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।  
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. "Sustainable development rests on a commitment to equity with future generations. In 1972 the United Nations Stockholm Conference on the Human Environment recognized that we had a responsibility to 'protect and improve' the environment for both present and future generations."

P. T. O.

Critically comment on the concept of sustainable development in the light of the above observation. Briefly analyze the steps taken by the international community to achieve sustainable development since Stockholm Conference to Rio+20 Conference.

“लम्बे समय तक जारी रहने योग्य विकास भावी पीढ़ियों के साथ साम्या के प्रति प्रतिबद्धता पर टिकता है। 1972 में मानवीय पर्यावरण पर यूनाइटेड नेशन्स स्टॉकहोम सम्मेलन में मान लिया गया था कि वर्तमान की तथा भविष्य की दोनों पीढ़ियों के लिये हमारा दायित्व है कि पर्यावरण को संरक्षित और सुधारा जाए।”

उपर्युक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लम्बे समय तक जारी रहने योग्य विकास की संकल्पना पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। स्टॉकहोम सम्मेलन से रियो+20 सम्मेलन तक लम्बे समय तक जारी रहने योग्य विकास की प्राप्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए।

20

2. What are the environmental issues dealt with by the Supreme Court in *Narmada Bachao Andolan vs Union of India* (AIR 2000 SC 3751)? Do you agree with the stand of Supreme Court on precautionary principle in this case? What is your view on the dissenting opinion of Justice Bharucha in this case?

नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

(ए०आई०आर० 2000 एस०सी० 3751) में उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय विवादक क्या हैं ?

क्या आप इस केस में पूर्वावधानीपरक सिद्धान्तों पर उच्चतम न्यायालय के रवैये से सहमत हैं ? इस केस में जस्टिस भरूचा की विसम्मत राय के बारे में आपके क्या विचार हैं ? 20

3. (a) What do you understand by polluter pays principle? Discuss its applicability in India with the help of decided cases.

प्रदूषक चुकाए सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? विनिश्चित केसों की सहायता से भारत में इसकी अनुप्रयोज्यता का विवेचन कीजिए । 10

- (b) “[I]t is remarkable that India was the first country in the world to enshrine environmental protection as a state goal in its Constitution.” Comment on the above statement with the help of constitutional provisions to protect environment. Is there any fundamental right to environment in India?

“यह उल्लेखनीय है कि विश्व में भारत अपने संविधान में राज्य के उद्देश्य के रूप में पर्यावरणीय संरक्षण को अधिष्ठापित करने वाला प्रथम देश था ।” पर्यावरण का संरक्षण करने के लिये संवैधानिक उपबंधों की सहायता से उपर्युक्त कथन पर टिप्पणी लिखिए । क्या भारत में पर्यावरण के प्रति कोई मूल अधिकार है ? 10

4. "Whenever a problem of ecology is brought before the court, the court is bound to bear in mind Article 48-A and 51-A(g) of the Constitution ... When the court is called upon to give effect to the Directive Principle and the fundamental duty, the court is not to shrug its shoulders and say that priorities are a matter of policy and so it is a matter for the policy-making authority. The least that the court may do is to examine whether appropriate considerations are borne in mind and irrelevancies excluded." Examine this observation of the Supreme Court in the light of *Sachidanand Pandey V. State of West Bengal* (AIR 1987 SC 1109).

“परिस्थिति विज्ञान की कोई समस्या जब कभी न्यायालय के समक्ष लाई जाती है तब न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48-A और 51-A(g) को अपने मस्तिष्क में रखने के लिये आबद्ध है। जब न्यायालय का निदेशक सिद्धान्तों और मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिये अवलम्ब लिया जाता है तब न्यायालय को इसे टालना तथा यह कहना नहीं होता है कि अग्रताएँ नीति के मामले हैं और उसी तरह यह नीति-निर्माता प्राधिकारी का मामला है। न्यायालय कम से कम इसकी जांच तो कर ही सकता है कि क्या समुचित विचारों को ध्यानगत रखा गया है तथा विसंगतियाँ अपवर्जित की गई हैं।” उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी की जांच *Sachidanand Pandey V. State of West Bengal* (AIR 1987 SC 1109) को ध्यान में रखते हुए कीजिए।

20

5. (a) Analyze the importance of the procedure laid down in Section 21 of the Water (Prevention and

Control of Pollution) Act, 1974 in the light of *Delhi Bottling Co. Pvt. Ltd. V. Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution* (AIR 1986 Delhi 152). Can a court issue directions to set up effluent treatment plant under Section 33 of the Water Act?

*Delhi Bottling Co. Pvt. Ltd. V. Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution* (AIR 1986 Delhi 152) को ध्यान में रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 21 में अधिकथित प्रक्रिया के महत्व का विश्लेषण कीजिये।

15

- (b) What do you understand by Air Pollution Control areas?

वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों से आपका क्या अभिप्राय है ?

5

6. (a) Examine the rule making powers of the Central Government under the Environmental (Protection) Act, 1986. Can the Central Government issue a rule under the Environmental (Protection) Act to combat climate change without resorting to enactment of a new law?

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की नियम निर्माण शक्तियों की जांच कीजिए। क्या केन्द्र सरकार नई विधि के अधिनियमन का अवलम्ब लिए बिना जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए पर्यावरण

P. T. O.

(संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम जारी कर सकती है ? 10

(b) What kinds of activities require Environmental Impact Assessment (EIA)? Explain the different stages involved in obtaining EIA.

किस प्रकार के क्रिया-कलापों के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (EIA) अपेक्षित है ? पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राप्त करने में समाहित भिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए ।

10

7. Discuss the jurisdictional scope of National Green Tribunal (NGT) in dealing with the legal rights of people pertaining to environment and providing relief and compensation for damages to persons and properties and environment. Which principle of law will NGT apply in case of accidents? What are the principles NGT is expected to apply while passing orders or award?

पर्यावरण के बारे में लोगों के विधिक अधिकारों के बारे में तथा व्यक्तियों, सम्पत्तियों और पर्यावरण को हुई हानि हेतु अनुतोष और प्रतिकर की व्यवस्था कराने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अधिकारिता सम्बन्धी परिव्याप्ति का विवेचन कीजिए । दुर्घटनाओं के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस विधि सिद्धांत को लागू करेगा ? अधिनिर्णय पर आदेश पारित करते समय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जिस विधि सिद्धान्त को लागू किए जाने की आशा है वह क्या है ?

20

8. (a) What are the circumstances in which the use of a forest land for non-forest purpose is justified? Whose approval is required to convert the forest land for non-forest purposes as per the Forest (Conservation) Act, 1980?

वे कौनसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि का प्रयोग न्यायोचित है? वन (परिरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार वनेतर प्रयोजनों हेतु वन भूमि को संपरिवर्तित करने के लिये किसका अनुमोदन अपेक्षित है?

10

- (b) What are the advantages of having absolute liability principle over strict liability principle?

आत्यंतिक दायित्व के सिद्धान्त को कड़े दायित्व के सिद्धान्त पर प्रधानता दिए जाने के क्या फायदे हैं?

10